



2026:AHC:67563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 12934 वर्ष 2026

दुर्गेश मौर्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अविनाश मणि त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: सुनील कुमार चौधरी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अविनाश मणि त्रिपाठी, विपक्षी पक्ष संख्या-4/प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार चौधरी और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रस्तुत आवेदन सत्र मामला संख्या-1623 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दुर्गेश मौर्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो धारा 363 भ०द०वि०, 366, 376(2)(एन) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6(जे)(2), थाना-खजनी, जिला गोरखपुर के साथ-साथ 11.05.2025 की आरोप पत्र और समन आदेश दिनांक 13.06.2025 के तहत सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय संख्या-आईएस.टी., गोरखपुर की अदालत में लंबित है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
 - (i) प्रस्तुत मामले के आवेदक और पीड़ित ने 26.02.2024 को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया है और उनकी शादी 22.03.2024 को पंजीकृत की



गई थी। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति इस आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या-4 के रूप में संलग्न की गई है।

(ii) 29.09.2024 को आवेदक और पीड़ित के विवाह से एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ था, जिसकी प्रति इस आवेदन में अनुलग्नक संख्या-5 के रूप में संलग्न की गई है।

(iii) आवेदक और पीड़िता, अपनी शादी संपन्न होने के बाद, एक ही छत के नीचे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगे, हालांकि, आवेदक को पुलिस ने 06.05.2025 को गिरफ्तार कर लिया और तब से वह जेल में बंद है।

(iv) प्रस्तुत मामले के पहले सूचनाकर्ता ने भी विवाह को स्वीकार कर लिया है और पीड़ित अब पहले सूचनाकर्ता के साथ रह रही है क्योंकि आवेदक उपरोक्त मामले के संबंध में जेल में है।

(v) पक्षकारों ने अपना विवाह बहुत पहले कर लिया है और एक बच्चे का जन्म भी हुआ है।

(vi) पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जब उसका बयान धारा 161 द०प्र०स० और धारा 164 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया गया था। दोनों बयानों में, उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था और उसने आवेदक के साथ शादी कर ली है। धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़िता ने कहा कि वह सात महीने के लड़के की मां है और उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। लड़के का जन्म आवेदक और पीड़िता के विवाह से हुआ था।

4. प्रतिपक्षी संख्या-4 के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार किया है और इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीड़ित की शादी आवेदक के साथ हुई है और आवेदक और पीड़ित के विवाह से एक बच्चे का जन्म हुआ है।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन विवाह और बच्चे के जन्म के तथ्य पर विवाद नहीं कर सका।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था जब धारा 161 द०प्र०स० और धारा 164 द०प्र०स० के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था, हालांकि, विवेचनाधिकारी ने पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता के हाई-स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 05.07.2007 है, इसलिए, कथित घटना के समय उसकी आयु लगभग 15 वर्ष और दस महीने थी। अभियोजन पक्ष का यह स्वीकार किया गया है कि भागने के बाद, पीड़िता ने आवेदक के साथ विवाह किया और आवेदक और पीड़िता के विवाह से एक बच्चे का जन्म हुआ और वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे, जब तक कि आवेदक को पुलिस द्वारा 06.05.2025 को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

7. जूही देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2005(13) एस.सी.सी. 376 पर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिलायंस रखा गया है; सुहानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2018 (3) एआईसीएलआर 183 और रीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2012 (2) एसीआर 2349 में इस न्यायालय के निर्णय; शाहीन परवीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2015 (7) ए.डी.जे. 713 और सुनील तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (धारा 482 द०प्र०स० संख्या-5471 वर्ष 2016 के तहत आवेदन), 21.10.2016 को संदर्भित किया गया।

8. आवेदक पर धारा 363 और 366 भ०द०वि० के तहत अपराध करने का आरोप है। धारा 363 भ०द०वि० में प्रावधान है कि जो कोई भी वैध संरक्षकता से किसी भी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे प्रावधान में प्रदान की गई सजा के संदर्भ में दंडित किया जाएगा।

9. धारा 361 भ०द०वि० के तहत "वैध संरक्षकता से अपहरण" को परिभाषित किया गया है। जब यह प्रावधान निकाला जाता है तो वह इस प्रकार है: -

"जो कोई भी * [सोलह] वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग को लेता है या लुभाता है, यदि कोई पुरुष, या ** [अठारह] वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, यदि एक महिला, या अस्वस्थ दिमाग का कोई भी व्यक्ति, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, ऐसे नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले



व्यक्ति के वैध अभिभावक को रखने के लिए, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कहा जाता है।

स्पष्टीकरण: इस धारा में "वैध अभिभावक" शब्दों में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनी रूप से ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई है।

अपवाद: यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति के कार्य तक विस्तारित नहीं होती है जो अच्छे विश्वास में खुद को एक नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो अच्छे विश्वास में खुद को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है।

10. धारा 366 भ०द०वि० में कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जा सके, उसे सजा दी जाएगी, जैसा कि प्रावधान में प्रावधान किया गया है। इस बात पर विचार करते समय कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने पर अपराध किया गया है या नहीं, अपराध के अवयवों पर जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है।

11. इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय ने मामले की जांच पर सामने आए तथ्यों की बारीकी से जांच की है। यह दिखाने के लिए अभिलेखों पर पर्याप्त सबूत हैं कि अभियोक्ता ने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है, साथ ही घटना की तारीख को वयस्कता की आयु भी प्राप्त कर ली है।

12. जूही देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य (2005) 13 एस.सी.सी. 376 में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ इसी तरह के तथ्य विचार के लिए आए, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोक्ता



जिसने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है, उसे संवैधानिक गारंटी के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। प्रासंगिक प्रस्तर-नीचे उद्धृत किया गया है: -

"2. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने अपनी उम्र के किसी अन्य व्यक्ति से शादी की थी और यहां 5वें प्रतिपक्षी, याचिकाकर्ता के पिता ने उक्त विवाह पर आपत्ति जताई थी। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता उस व्यक्ति के साथ भाग गया था और याचिकाकर्ता-5वें प्रतिपक्षी के पिता ने शिकायत दर्ज की है और याचिकाकर्ता को सीजेएम, पटना के समक्ष पेश किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बड़ी थी और स्वेच्छा से अपने पति के साथ चली गई थी। याचिकाकर्ता के पिता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता नाबालिग था और उम्र का सवाल मेडिकल बोर्ड को भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि 17.05.2003 तक, याचिकाकर्ता की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता के पिता ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और तर्क दिया कि उसकी जन्मतिथि 12.10.1985 है और उसने बहुमत प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि 17.05.2003 को भी उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक रही होगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उसने वयस्कता प्राप्त कर ली होगी और रिमांड होम में उसका रहना न्याय के हित में नहीं होगा और हमें लगता है कि रिमांड होम में उसका निरंतर रहना हानिकारक होगा और वह उस व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर वातावरण में होगी जिससे उसने कथित तौर पर शादी की थी।

13. श्रीमती रीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या-10180 वर्ष 2012) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 24.5.2012 को निर्णय दिया कि अभियोक्ता के भागने के शुद्ध और सरल मामले में यह देखा जाना चाहिए कि संवैधानिक गारंटी के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के उसके अधिकार में कटौती या अतिक्रमण नहीं किया जाता है। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं: -



"हम मामले के तथ्यों से पाते हैं कि यह याचिकाकर्ता, श्रीमती रीना के अब्दुल्ला और याचिकाकर्ता के साथ भागने का एक शुद्ध और सरल मामला था, उसके बाद सीधे उसके घर चला गया जहां से वह बरामद हुई प्रतीत होती है। लड़की की उम्र के संबंध में कुछ विवाद था, लेकिन हम प्रस्तुत याचिका के पृष्ठ 20 पर दिखाई देने वाले तर्क से पाते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महाराजगंज ने उसकी 18 वर्ष की आयु का आकलन किया था। इस प्रकार, महिला निर्विवाद रूप से 18 वर्ष से अधिक थी, यदि हम चिकित्सकीय रूप से मूल्यांकन की गई आयु में तीन वर्ष जोड़ते हैं। किसी भी स्कूल दस्तावेज़ में दर्ज उम्र और डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्र के बीच संघर्ष होने के मामले में हमारे विचारशील विचार में, अदालत को पीड़ित की उम्र का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद दिए गए डॉक्टर की राय पर कार्य करने की ओर झुकना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हो। उम्र पर चिकित्सा राय सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन यह आम तौर पर स्वीकृति है और यह उम्र का आकलन करने की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जैसे, उम्र और वास्तविक आयु का आकलन करने में किसी प्रकार का मार्जिन होने के बावजूद, संभावना हो सकती है कि मूल्यांकन की गई आयु लगभग सटीक है।

हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अदालत को स्कूल के दस्तावेजों में दर्ज उम्र पर विचार करने की तुलना में चिकित्सा आयु पर विचार करने की ओर झुकना चाहिए। इसके अलावा, इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता, श्रीमती रीना 3-3-2011 को अब्दुल्ला के साथ भाग गई थी और उसके घर में घुस गई थी और वहां रह रही थी। ... तथ्यों के वर्तमान सेट के तहत, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह भागने का एक सरल और



शुद्ध मामला है और इस तरह किसी भी अपराध या अपराध को स्वीकृत तथ्यों के तहत गठित नहीं कहा जा सकता है।

... किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में कोई उम्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एक इंसान के रूप में पैदा हुआ है और जो भारत में रहता है, भले ही वह भारतीय न हो, उसे संवैधानिक गारंटी के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। कोई भी आदेश जो ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है या अतिक्रमण करता है और उसे हमेशा संविधान की आवश्यकताओं और सुरक्षा उपायों से कम माना जाता है और इस तरह, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करना होगा।"

14. प्रस्तुत मामले में, विचार करने का बिंदु यह है कि क्या आवेदक ने पीड़ित के संदर्भ में अपराध किया है या नहीं। यहां रिट याचिका संख्या-3519(एमबी) वर्ष 2015 (शाहीन परवीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित इस न्यायालय के दिनांक 23.07.2015 के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जहां इस न्यायालय ने कहा कि एक लड़की जिसने विवेक की आयु प्राप्त कर ली है और बालिग होने की कगार पर थी और यह जानने में सक्षम है कि उसके लिए क्या अच्छा था और क्या बुरा था, उसे प्रलोभन का शिकार नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब पीड़िता/लड़की का मामला खुद यह है कि यह उसकी पहल पर था और उसके स्वैच्छिक कार्य के कारण वह लड़के के साथ गई थी और उससे शादी कर ली थी। ऐसी परिस्थितियों में, लड़की/पीड़ित की इच्छा को देखना आवश्यक है। धारा 361 भ०द०वि० की सामग्री पर तदनुसार विचार करने की आवश्यकता है, न कि यांत्रिक या तकनीकी व्याख्या में इस मामले में धारा 363 और 366 भ०द०वि० के तहत आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया था, जहां अभियोक्ता को विवेक की आयु प्राप्त करने और 17 वर्ष से कम उम्र की पाई गई थी। अभियोक्ता ने बयान दिया कि उसका न तो अपहरण किया गया था और न ही उसका अपहरण किया गया था जो स्वेच्छा से और जानबूझकर आरोपी के साथ गई थी। वह याचिकाकर्ता संख्या-2 के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही है और 31 सप्ताह की गर्भावस्था के साथ एक गर्भवती मां थी। इस न्यायालय ने आरोप पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया



कि तकनीकी की वेदी पर पर्याप्त न्याय का बलिदान नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"18. याचिकाकर्ता संख्या-1 पीड़िता/अभियोक्ता सबसे अच्छा गवाह होगा, बल्कि धारा 363 भ०द०वि०/366 के तहत अपराध करने का एकमात्र गवाह होगा। निश्चित रूप से, पीड़िता अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेगी, जैसा कि धारा 164 द०प्र०स० के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में स्पष्ट किया गया है, और इसलिए मुकदमे के परिणामस्वरूप बरी कर दिया जाएगा। मुकदमे के दौरान, मामले को अभियोजन/बचाव और न्याय करने में काफी संख्या-में मानव घंटे बर्बाद होंगे। कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और मुकदमे की पूरी कवायद व्यर्थ होगी क्योंकि पीड़िता ने घोषणा की है कि उसे पीड़ित या अपहरण नहीं किया गया था।

19. अभिलेखों से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही इसलिए शुरू की गई है क्योंकि अभियोक्ता/पीड़ित (प्रतिपक्षी संख्या-4) की मां ने याचिकाकर्ता संख्या-2 के साथ अपनी बेटी की शादी को स्वीकार नहीं किया है।

20. मामले में, अभिलेखों पर आए सबूतों के बावजूद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्यवाही रद्द नहीं की जाती है, याचिकाकर्ता संख्या-2 को आपराधिक आरोपों का सामना करने और मुकदमे की पीड़ा से गुजरने की आवश्यकता होगी।

21. हमने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि यदि याचिकाकर्ता संख्या-2 पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता संख्या-1/कथित पीड़ित का वैवाहिक जीवन बाधित हो जाएगा। उसके पति को जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है।



22. यदि कोई नाबालिग, अपने स्वयं के, अपने माता-पिता की संरक्षकता को छोड़ देती है और लड़के द्वारा अपने माता-पिता की संरक्षकता को छोड़ने में निभाई गई किसी भी भूमिका के बिना और उसे किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन आदि के अधीन किए बिना और अभियुक्त से किसी भी प्रस्ताव या वादे के बिना शामिल हो जाती है, तो धारा 363 भ०द०वि० के तहत दंडनीय कोई अपराध तब नहीं किया जाएगा जब लड़की की आयु 17 वर्ष से अधिक हो और वह यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो कि वह क्या कर रही है। बेशक, यदि आरोपी लड़की को उकसाता है या लुभाता है और यह नाबालिग को उसके अभिभावक की हिरासत छोड़ने और आरोपी के साथ रहने और जाने में प्रभावित करता है, तो न्यायालय के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि नाबालिग स्वेच्छा से आरोपी के पास आया था। यदि पीड़िता/अभियोक्ता स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, लड़के के साथ जाती है, तो कानून लड़के पर उसे उसके पिता के घर वापस ले जाने या यहां तक कि उसे उसके साथ न जाने के लिए कहने का कर्तव्य नहीं देता है।

27. रिट न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं के कल्याण की उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता है, खासकर जब मुकदमे का अभ्यास व्यर्थ होने जा रहा है, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

28. ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय आश्वस्त है कि न्यायालय की प्रक्रिया और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में आक्षेपित कार्यवाही शुरू की गई है। बेटे की पसंद के विवाह के खिलाफ एक व्यक्तिगत द्वेष को आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के आधार पर निपटाया जा रहा है, जो कानून में अनुमेय नहीं होगा। इस तरह के अभियोजन से याचिकाकर्ताओं में उनके विवेक के अनुसार शादी करने के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा, खासकर जब यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि विवाह शून्य है।



29. अभियोजन एजेंसी का यह रुख कि पीड़िता अभियुक्त/याचिकाकर्ता संख्या-2 की कंपनी में शामिल होने पर वयस्कता की आयु से कुछ महीने कम थी, और इसलिए अपराध किया गया है, यदि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जाए तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अभिलेखों पर आया है कि अभियोक्ता एक गर्भवती मां है और 31 सप्ताह की गर्भावस्था को जन्म दे रही है। इस तथ्य के साथ अभियोक्ता का बयान भी है जिसमें उसने कहा है कि उसका न तो अपहरण किया गया था और न ही उसका अपहरण किया गया था, बल्कि वह याचिकाकर्ता संख्या-2 के साथ अपनी पत्नी के रूप में रह रही है। यह अभियोक्ता ही है जो अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से, जानबूझकर और अभियुक्त के बजाय अभियोक्ता को वैध अभिभावक की हिरासत से बाहर ले गई थी; पीड़िता खुद याचिकाकर्ता संख्या-2 के साथ भाग गई थी। न्यायालय की सुविचारित राय में, तकनीकी की वेदी पर पर्याप्त न्याय का बलिदान नहीं किया जा सकता है, जैसा कि जांच एजेंसी द्वारा निष्कर्ष निकाला जा रहा है।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता संख्या-2 को धारा 363 भ०द०वि० के तहत या धारा 361 भ०द०वि० सपठित धारा 366 भ०द०वि० के तहत अपराध करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

15. एस.सी. 942 AIR1965 में रिपोर्ट किए गए एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 361 भ०द०वि० के अर्थ की व्याख्या की है और माना है कि यदि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी में शामिल हो गई थी तो ऐसे मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने उसे संहिता की धारा 361 के अर्थ के भीतर वैध अभिभावक के संरक्षण से दूर कर दिया था। एस. वरदराजन (उपरोक्त) का निर्णय पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"11. हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "लेने" और एक नाबालिग को किसी व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति देने के बीच अंतर है। दोनों अभिव्यक्तियाँ समानार्थी नहीं हैं, हालांकि हम खुद को यह निर्धारित करने से बचाना चाहेंगे कि किसी भी कल्पनीय परिस्थिति में



भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रयोजनों के लिए दोनों का अर्थ एक ही नहीं माना जा सकता है। हम अपने आप को वर्तमान जैसे मामले तक सीमित रखेंगे जहां आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से ले जाए गए नाबालिग ने अपने पिता की सुरक्षा को छोड़ दिया, यह जानते हुए कि वह जो कर रही थी उसका पूरा महत्व जानने की क्षमता स्वेच्छा से आरोपी व्यक्ति में शामिल हो जाती है। ऐसे मामले में हमें नहीं लगता कि अभियुक्त को अपने वैध अभिभावक को रखने से दूर ले जाया जा सकता है। इस तरह के मामले में कुछ और दिखाया जाना चाहिए और वह है आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन या अभिभावक के घर छोड़ने के नाबालिग के इरादे के निर्माण में उसके द्वारा सक्रिय भागीदारी।

12. हालांकि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि हालांकि नाबालिग के पिता की सुरक्षा छोड़ने से ठीक पहले आरोपी द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, उसने कुछ पहले चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था या राजी किया था। हमारी राय में, यदि उन चीजों में से एक को स्थापित करने के लिए सबूत की कमी है, तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि आरोपी नाबालिग को वैध अभिभावक के रखने से बाहर ले जाने का दोषी है, केवल इसलिए कि वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या एक घर को छोड़ चुकी है जहां उसके अभिभावक ने उसे रखा था, आरोपी के साथ शामिल हो गया और आरोपी ने उसे अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर अपने अभिभावक के घर वापस न लौटने के अपने डिजाइन में उसकी मदद की। इसमें कोई संदेह नहीं है, अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को लड़की के इरादे की पूर्ति की सुविधा के रूप में माना जा सकता है। यह हिस्सा, हमारी राय में, नाबालिग को अपने वैध अभिभावक के रखने से बाहर निकलने के लिए एक प्रलोभन से कम है और इसलिए, "लेने" के समान नहीं है।

उस धारा के तहत किसी अपराध के संबंध में जो भी स्थिति हो सकती है और यहां तक कि यह मानते हुए कि एक नाबालिग कानून में अपने वैध



अभिभावक की संरक्षकता को नहीं छोड़ सकता है, जिस कारण से हम पहले ही बता चुके हैं, आरोपी व्यक्ति जिसके साथ वह बाद में पाई जाती है, उसे उसके अभिभावक के रखने से बाहर ले जाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि कुछ और स्थापित न हो जाए।

यह इंगित करने के बाद कि "लेना" और "लुभाना" शब्दों के बीच एक आवश्यक अंतर है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि नाबालिग का मानसिक रवैया लेने के मामले में प्रासंगिक नहीं है और "लेना" शब्द का अर्थ है जाना, एस्कोर्ट करना या कब्जे में लाना। लेकिन इन टिप्पणियों को उस मामले में पाए गए तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। क्योंकि, यह पाया गया था कि जिस नाबालिग लड़की का आरोपी पर अपहरण करने का आरोप लगाया गया था, उसे आरोपी ने तब राजी किया था जब वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए अपने घर से बाहर गई थी, उसके साथ जाने के लिए और उसके द्वारा दूसरे गांव ले जाया गया था और उसके चाचा के घर में तब तक रखा गया था जब तक कि उसे बाद में चाचा द्वारा उसके पिता के पास वापस नहीं कर दिया गया। इस प्रकार, यहां आरोपी व्यक्ति द्वारा अनुनय का एक तत्व था जो लड़की की इच्छा को लेकर आया और इससे सभी फर्क पड़ता है। इसलिए, हमारी राय में, इनमें से कोई भी निर्णय राज्य की सहायता का नहीं है।

हम अभिलेखों पर मौजूद सामग्री पर संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए, वह बरी होने का हकदार है। तदनुसार हम अपील की अनुमति देते हैं और उस पर दी गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम उरव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या-(एस) में। 41/2021, 10.01.2025 को निर्णय लिया गया, ने अपीलकर्ता को दोषसिद्धि के साथ-साथ इस आधार पर लगाई गई सजा को भी रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़ित ने एक-दूसरे से शादी की थी।



17. इसी तरह, दसारी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य (2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 936 में रिपोर्ट किए गए मामले में, जिसमें समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। दसारी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर-8 से 10 को निम्नानुसार पढ़ा गया है: -

"8. चूंकि, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से शादी कर ली है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि का आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेजे जाने पर विनाशकारी परिणाम होगा जो बदले में शिकायतकर्ता के साथ उसके वैवाहिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 जून, 2023 के आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित 9 अप्रैल, 2021 के फैसले को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

18. प्रस्तुत मामले के तथ्य उपरोक्त निर्णयों से काफी मिलते-जुलते हैं। यहां भी मुझे लगता है कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसके अनुसार वह कथित अपराध की तारीख को स्वेच्छा से आवेदक आरोपी के साथ गई थी। इसके बाद, उसने उससे शादी कर ली। इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 (जे)(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376 (2)(एन) के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है। पुलिस ने बिना सोचे-समझे यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और दुर्भाग्य से विचारण न्यायालय ने भी इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। दूसरे, यहां सवाल उठता है कि क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6(जे)(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376 (2)(एन) के तहत आपराधिक मामले की कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 द०प्र०स० और 528 बी.एन.एस.एस. के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन में रद्द किया जा सकता है, यदि पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया है और लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं और विवाह से बच्चे का जन्म हुआ है।

19. पुलिस निरीक्षक द्वारा के. दंडपाणि बनाम राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1056 और मफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 433 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपी ने अभियोक्ता के साथ विवाह किया था और दूसरी बात, अदालत उक्त तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकती है। चूंकि के. दंडपाणि (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय छोटा है, इसलिए, इसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

"अनुमति दी गई।

अपीलकर्ता जो अभियोक्ता का मामा है, वलायार समुदाय से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य में सबसे पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक मजदूरी पर लकड़हारे का काम करता है। उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण (पाँकसो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 5(j)(ii) के तहत बलात्कार करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त अपराधों को करने के लिए मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था और 31.10.2018 को सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुपुर द्वारा 10 साल की अवधि के लिए कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के एक आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री एम.पी.पार्थिवन ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने उससे शादी करने के वादे पर अभियोक्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने कहा कि, वास्तव में, उन्होंने अभियोक्ता से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं।



अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और उसे पूर्ण न्याय करना चाहिए और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के पारिवारिक जीवन को परेशान करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है।

08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभियोक्ता का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्ता का बयान अभिलेखों पर रखा गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है और वह एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है।

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने अपीलकर्ता को इस आधार पर कोई राहत देने का विरोध किया कि अभियोक्ता अपराध की तारीख को 14 वर्ष की थी और उसने 15 वर्ष की आयु में पहले बच्चे को जन्म दिया था और जब वह 17 वर्ष की थी तब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच विवाह कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा उसे राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता अभियोक्ता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित विचार है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा जो अभियोक्ता का मामा है, इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रद्द किया जाना चाहिए। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकता है और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन को परेशान नहीं कर सकता है। हमें तमिलनाडु में मामा के साथ लड़की की शादी की प्रथा के बारे में सूचित किया गया है।



उपरोक्त उल्लिखित कारणों से, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में अलग कर दिया जाता है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

यदि अपीलकर्ता अभियोक्ता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या अभियोक्ता की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।

20. मेरी सुविचारित राय में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6(जे)(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376 (2)(एन) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता ने उपरोक्त धाराओं के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि पीड़िता ने किसी भी समय यह नहीं कहा कि आवेदक द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6(जे)(2) सपठित धारा 363 भ०द०वि०, 366 और 376 (2)(एन) के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने का मूल घटक गायब है। तत्स्य विपरीत, पीड़िता ने आवेदक के साथ विवाह कर लिया है और विवाह से एक बच्चे का जन्म हुआ है और वे पिछले कई वर्षों से एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। यदि इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाता है, तो आवेदक और बच्चे के साथ पीड़ित को कानूनी चोट लग सकती है और आवेदक का मामला यहां ऊपर उल्लिखित मामलों से पूरी तरह से आच्छादित किया जाता है।

21. यहां ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए, प्रस्तुत आवेदन सफल होता है और इसकी अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है।

22. धारा 363 भ०द०वि०, 366, 376(2)(एन) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6(जे)(2) के तहत केस अपराध संख्या-159 वर्ष 2023 से उत्पन्न सत्र मामला संख्या-1623 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दुर्गेश मौर्य) की पूरी कार्यवाही, साथ ही सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय के द्वारा आवेदक के खिलाफ आई.एस.टी., गोरखपुर की पूरी कार्यवाही को रद्द/अपास्त किया जाता है।



23. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। 24. चूंकि कार्यवाही के साथ-साथ 11.05.2025 को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, इसलिए, विचारण न्यायालय को निर्देश आवेदक को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए।

मार्च 31, 2026

ए.पी. पांडे

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.